आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 05.07.2026 समय : 1905

<><><><><><><>

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की छह दिन की यात्रा पर रवाना होंगे।
2. केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए सात दिन के भीतर जवाब मांगा।
3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त माह में विषेश लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
4. कर्नाटक में होने वाली उनतालीसवीं नेशलन अंडर–11 चेस चैम्पियनशिप–2026 में भाग लेने के लिए द्वीप समूह से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की छह दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे।

<><><><><><><>

सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। भारत में डिजिटल कानूनों के अन्तर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले, मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे।

<><><><><><>

भारत, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा कल से 8 जुलाई के बीच आयोजित किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति में उभरते मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूह उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर सहयोग और संवाद के लिए प्रमुख अंतर–सरकारी मंच है।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के नागरिकों और संगठनों से स्वतंत्रता दिवस, 2026 के अवसर पर उपराज्यपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार कला, वाणिज्य, शिक्षा, खेलकूद व संस्कृति और समाज कल्याण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 24 जुलाई शाम 5 बजे तक सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ गोपनीय सेल, सचिवालय के पास जमा या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए सरकारी अधिकारी और गैर–सरकारी व्यक्ति दोनों ही पात्र हैं।

<><><><><><>

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21, 22 और 23 अगस्त, को विषेश लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस सिलसिले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 35 मामलों की पहचान की है। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 11 जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर 1 बजे तक पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच में प्री–लोक अदालत का आयोजन करेगा। पहचाने गए मामलों की आधिकारिक सूची और नोटिस जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

<><><><><><>

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल – राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना – आईसीएमआर–माइंड्स, ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। परिषद के

महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद, जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए डेटा–आधारित, स्केलेबल प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों में अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी। उन्होंने कहा कि सहभागी संस्थानों और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ निरंतर सहयोग के माध्यम से, परिषद भारत के लोगों के लिए किफायती, मानकीकृत और उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

<><><><><><><>

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस उच्च शिक्षण संस्थान के घटक महाविद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर में विभिन्न 7 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी 7 जुलाई तक कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

<><><><><><><>

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ओडीएल और ऑनलाइन मोड में सभी कार्यक्रमों के जुलाई सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार समर्थ इग्नू पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन 12 जुलाई को डेयरी फार्म स्थित ANCA चेस सेंटर, में अंडर–11 चयन ट्रायल आयोजित करेगा। इस इवेंट का उद्देश्य द्वीप समूह से दो लड़कों और दो लड़कियों का चयन करना है, जो 2 से 8 अगस्त तक कर्नाटक में होने वाली उनतालीसवीं नेशनल अंडर–11 चेस चौंपियनशिप–2026 में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ष 2026–2027 के लिए AICF पंजीकरण ज़रूरी है। इच्छुक खिलाड़ी 10 जुलाई तक डेरी फार्म स्थित ANCA कार्यालय में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच अपना पंजीकरण करा सकते है। अधिक जानकारी के लिए फोन संख्या 99–33–217–055 पर संपर्क कर सकते है।

<><><><><><><>

भारतीय तटरक्षक बल बाईस जुलाई को ब्रिजगंज स्थित बफल रेंज में फायरिंग अभ्यास करेगा। यह अभ्यास सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से अपने वाहनों एवं पशुओं को फायरिंग रेंज से दूर रखने को कहा गया है।

<><><><><><><>

एसोसिएशन ऑफ़ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ़ इंडिया – अंडमान चैप्टर ने द्वीप समूह में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वीर सावरकर पार्क, बर्मानाला में तट सफ़ाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस सफ़ाई अभियान का नेतृत्व ADTOI – अंडमान चौप्टर के चेयरमैन एम. विनोद ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि द्वीप समूह के साफ़–सुथरे समुद्र तट इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पर्यटन संपत्तियों में से हैं और उन्हें संरक्षित करना हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने पर्यटन से जुड़े लोगों, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार व्यवहार अपनाने और द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में योगदान देने का आग्रह किया। इस पहल का उद्देश्य समुद्र तटों को साफ़ रखने, तटीय इकोसिस्टम की रक्षा करने और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाना था। स्वयंसेवकों ने समुद्र तट से प्लास्टिक का कचरा और अन्य गंदगी इकट्ठा की और पर्यटकों को सिंगल–यूज़ प्लास्टिक से बचने और सफ़ाई बनाए रखने के बारे में जागरूक किया।

<><><><><><><>